सं.10(3)/2018-समन्वय

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

***

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 20 दिसंबर, 2018

विषय: नवंबर, 2018 के लिए भारी उद्योग विभाग का मासिक सार।

अधोहस्ताक्षरी को नवंबर, 2018 के लिए **भारी उद्योग विभाग (डीएचआई)** और **लोक उद्यम विभाग (डीपीई)** से संबंधित मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

दिनेशपालसिंह

(दिनेश पाल सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

फोन: 20361045

सेवा में

1. मंत्री परिषद के सभी सदस्य।
2. उप सभापति, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली
3. नीति आयोग, योजना भवन (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित), नई दिल्ली
4. श्री सितांशु कर, मुख्य प्रबंध निदेशक, मीडिया एंड कम्युनिकेशन (एम एंड सी), ए-विंग, प्रथम-तल, कमरा न-101,सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों के सचिव।
2. अध्यक्ष, यूपीएससी, शाहजहां रोड, नई दिल्ली -110069
3. भारत के राष्ट्रपति (राष्ट्रपति के सचिव) के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
4. भारत के उप-राष्ट्रपति (उप-राष्ट्रपति के सचिव) के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
5. भारत के प्रधान मंत्री के निजी सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
6. भास्कर दास गुप्ता, निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
7. निदेशक, अंतर-राज्य परिषद्, एमआईआईए, विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली -110011
8. सचिवों के प्रधान स्टॉफ अधिकारी (सी और पीसी)
9. श्री सैमसुल हक, अवर सचिव (वेज), लोक उद्यम विभाग (डीपीई), कमरा नं-424, ब्लॉक-14, सी. जी. ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

(A) DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY (DHI):

1. A German delegation led by Prof. Dr. Claudia Warning, Director General, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Germany met to Secretary, DHI on 30.11.2018 to exchange information on electric mobility outlook with a view to explore closer cooperation between the two countries on the subject of Electric Mobility.

2. With the approval of Finance Minister, the outlay of ongoing scheme of "Faster Adoption and Manufacturing of Electric (and Hybrid) Vehicle in India" (FAME- India) has been increased from Rs 795 crores to Rs 895 crores to promote mass adoption of electric vehicles.

3. With an aim to boost production of electric Vehicles, Secretary, DHI had a meeting with Finance Secretary to discuss duty structure on electric vehicles and its components on 20.11.2018 following which recommendations were sent in writing to Department of Revenue for further action.

4. Public Procurement (Make in India) (Revised) order for automobile and auto components was issued on 19.11.18.

5. HMT (International) has supplied 250 advanced battery e-Rickshaws to Senegal at an estimated cost of Rs.6.25 crore. The e-Rickshaws were handed over to the Ambassador of Republic of Senegal on 16.11.2018 in the presence of Hon'ble External Affair Minister.

6. HMT's Hyderabad Unit has designed, developed, manufactured and assembled a 3-Axis CNC Vertical Facing Mill for supply to ISRO's Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota (SDSC SHAR) for machining of solid rocket motors. ISRO will be able to increase production of solid rocket motors for launching of more satellites with this machine. It is a state-of-art CNC machine for machining of various kinds of Solid Rocket Motors. This machine is an import substitute.

7. As a part of Skill India, Mr. Francis Lijo, an Apprentice Trainee who did his Apprenticeship Training as "Turner" at HMT Machine Tools Limited, Kalamassery has won the International Skill Competition (ISK-2018) in the Trade "CNC Turning" held at Moscow recently.

8. In response to the Expression of Interest (RoI) floated by the Resolution Professional (RP) seeking a Resolution Plan for Hindustan Paper Corporation (HPC), interest has been received from 2 bidders by the RP. The Committee of Creditors (CoC) has filed an application in NCLAT in the appeal filed by the CMD, HPC against the NCLT order dated 13.6.2018 (triggering Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) against HPC) to apprise NCLAT about the progress of CIRP. DHI has sought the advice of the Ministry of Law and the Department of Expenditure, as directed by the Cabinet Secretariat on disinvestment of Hindustan Newsprint Ltd. and revival/closure of HPC.

9. Under the Scheme for "Enhancement of Competitiveness of Indian Capital Goods Sector" with 80% funding from DHI and 20% funding from Industry, the Central Manufacturing Technology Institute,

(B) DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES (DPE):

1. Hon'ble Prime Minister chaired a meeting on follow up action on CPSEs Conclave 2018 on 05.11. 2018. DPE made a detailed presentation in the meeting and briefed Hon'ble Prime Minister along with concerned Secretaries on the action plans of CPSEs in important sectors such as Petroleum, Power, Coal, Defence Production, Fertilizers, Heavy Industry etc. The action points emerging from the meeting have been communicated by DPE to concerned Ministries/Departments for implementation.

2. As per direction of ACC, the following instructions have been issued to Administrative Ministries/Department for information and compliance:
   (i) Prior concurrence of DPE and PESB to fill up board level posts by the Search-cum-Selection Committee mode instead of the standard PESB route to be dispensed with. Such proposals for exemption are to be considered directly by the ACC without routing them through DPE and/or PESB, provided that the concerned administrative Ministry records the reasons for seeking exemptions with the approval of the Minister-in-charge.
   (ii) The period of lien shall be deemed to have been uniformly extended from the existing five years to six years in case where the Board level appointee in a CPSE is holding lien on a below Board level post in the same or any other CPSE

3. The meeting of Search Committee was held on 28.11.2018 to consider the proposals for appointment of 7 non-official Directors on the Boards of CPSEs under various administrative Ministries/ Departments.

4. The Inter-Ministerial Committee (IMC) completed the MoU Evaluation exercise for the year 2017-18 in respect of 165 CPSEs (33 meetings were held during this month).

5. A training programme on "Vigilance Awareness/Preventive Vigilance Practices" was organized in association with National Productivity Council, New Delhi during 30th October to 1st November, 2018 in Goa.

6. DPE submitted the monthly information for CAPEX of select CPSEs to PMO on 9th November, 2018.

****

(A). भारी उद्योग विभाग (डीएचआई):

1. इलैक्ट्रिक मोबिलिटी के विषय पर दोनों देशों के बीच निकटतम सहयोग को बढ़ावा देने के मद्देनजर इलैक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए डॉ. क्लोडिया वार्निंग, महानिदेशक, आर्थिक सहयोग और विकास संघीय मंत्रालय (बीएमजेड), जर्मनी की अगुआई में एक जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 30.11.2018 को सचिव, भारी उद्योग विभाग से मुलाकात की।

2. वित्त मंत्री के अनुमोदन से विद्युत वाहनों के व्यापक अंगीकरण को बढावा देने के लिए "भारत में इलैक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण" (फेम-इंडिया) की जारी योजना के परिव्यय को 795 करोड़ से बढाकर 895 करोड़ किया गया है।

3. विद्युत वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्युत वाहनों और इसके कलपुर्जों की शुल्क संरचना पर चर्चा करने के लिए दिनांक 20.11.20108 को सचिव, भारी उद्योग विभाग वित्त सचिव के साथ बैठक में शामिल हुए जिसके अनुपालन में आगे की कार्रवाई करने हेतु लिखित में सिफारिशें राजस्व विभाग को भेजी गई।

4. दिनांक 19.11.2018 को ऑटोमोबाइल और ऑटो कलपुर्जों हेतु सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया) (संशोधित) आदेश जारी किया गया।

5. एचएमटी (अन्तर्राष्ट्रीय) ने 6.25 करोड़ की अनुमानित लागत पर सेनेगल को 250 उन्नत बैटरी ई-रिक्शाओं की आपूर्ति की। यें ई-रिक्शा माननीय विदेश मंत्री की उपस्थिति में दिनांक 16.11.2018 को राजदूत, सेनेगल गणराज्य को सौंपी गई।

6. एचएमटी की हैदराबाद युनिट ने ठोस रॉकेट मोटर्स की मशीनिंग के लिए इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा (एसडीएससी एसएचएआर) को एक 3-एक्सिस सीएनसी वर्टिकल फेसिंग मिल को डिजाइन, विकसित, निर्मित और असेम्बल किया है। इसरो इस मशीन से और अधिक उपग्रहों को लॉंच करने के लिए ठोस रॉकेट मोटर्स के उत्पादन को बढाने में सक्षम हो सकेगा। विभिन्न प्रकार के सॉलिड रॉकेट मोटर्स की मशीनिंग के लिए यह एक नवीनतम सीएनसी मशीन है। यह मशीन आयात का एक विकल्प है।

7. कौशल भारत के एक भाग के रूप में, श्री फ्रांसिस लिजो, एक अप्रैंटिस प्रशिक्षु, जिसने एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, कलामसेरी में ''टर्नर'' के रूप में अप्रैंटिशिप ट्रेनिंग प्राप्त की है, ने हाल ही में मॉस्को में आयोजित ट्रेड "सीएनसी टर्निंग" में अन्तराष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता (आईएसके - 2018) जीती है।

8. प्रस्ताव पेशेवर (आरपी) द्वारा हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन (एचपीसी) हेतु प्रस्ताव योजना प्राप्त करने के लिए आमंत्रित की गई रुचि की अभिव्यक्ति के जवाब में, आरपी को दो बोलियां प्राप्त हुई हैं। लेनदारो की समिति (सीओसी) ने सीआईआरपी की प्रगति के बारे में एनसीएलएटी को अवगत कराने के लिए दिनांक 13.06.2018 के एनसीएलटी के आदेश [एचपीसी के विरूद्ध कार्पोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया आरंभ करना (सीआईआरपी)] के विरुद्ध सीएमडी, एचपीसी द्वारा दायर अपील में एनसीएलटी में एक आवेदन दायर किया है। भारी उद्योग विभाग ने हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि. के विनिवेश और एचपीसी के पुनरूद्धार/बंदीकरण पर मंत्रिमंडल के निदेश के अनुसार विधि मंत्रालय और व्यय विभाग से सलाह मांगी है।

9. भारी उद्योग विभाग से 80% और उद्योग से 20% के निधियन के साथ "भारतीय कैपिटल गुड्स सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि" हेतु योजना के तहत, केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर ने भारत के पहले स्वदेशी हाई स्पीड शटल रहित रैपियर लूम (400 आरपीएम) को डिजाइन, विकसित और इसका सृजन किया है। जिससे भारतीय वस्त्र मशीनरी विनिर्माताओं के स्थानीय और वैश्विक बाजार में मुकाबला करने में सक्षम बनाने की संभावना है। इस करघे का कार्य-निष्पादन अन्तराष्ट्रीय बेंच मार्क के समकक्ष करघे के बराबर है। प्रोटोटाइप मशीन को उद्योग स्टेकहोल्डरों के पास परीक्षण संचालन हेतु भेज दिया गया है। इस मशीन की व्यावसायिक घरेलू उत्पादन से ऐसे करघों के लिए प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ की आयात निर्भरता के कम होने की संभावना है।

10. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 30.11.2016 को आयोजित अपनी बैठक में केरल सरकार को इंस्ट्रुमेंन्टेशन लिमिटेड (आईएल) की पलक्कड़ युनिट के अंतरण हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया। इसके बाद भारत सरकार (भारी उद्योग विभाग), केरल राज्य

(B) **<u>लोक उद्यम विभाग (डीपीई):</u>**

1. माननीय प्रधानमंत्री ने 5 नवंबर,2018 को सीपीएसईज कॉनक्लेव 2018 पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की । लोक उद्यम विभाग ने बैठक में विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया और पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला, रक्षा उत्पादन, उर्वरक, भारी उद्योग आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सीपीएसईज की कार्य योजनाओं पर संबंधित सचिवों के साथ माननीय प्रधान मंत्री को संक्षिप्त विवरण दिया। बैठक में उठे कार्य बिन्दुओं को लोक उद्यम विभाग द्वारा कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया है।।

2. एसीसी के निदेश अनुसार, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को सूचना और अनुपालन के लिए निम्नलिखित अनुदेश जारी किए गए हैं :
   (i) मानक पीईएसबी रुट के स्थान पर जांच एवं चयन समिति मोड के द्वारा बोर्ड स्तर के पदों को भरने के लिए लोक उद्यम विभाग और पीईएसबी की पूर्व सहमति प्रदान करना। छूट संबंधी ऐसे प्रस्तावों पर, डीपीई और/अथवा पीईएसबी के माध्यम से रुटिंग किए बिना, एसीसी द्वारा प्रत्यक्ष रुप से विचार किया जाना, बशर्ते कि प्रभारी-मंत्री केअनुमोदन से छूट मांगने संबंधी कारणों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा रिकार्ड किया जाए।
   (ii) ऐसे मामले में, जहां सीपीएसई में बोर्ड स्तर नियुक्ती अपने अथवा किसी अन्य सीपीएसई में बोर्ड स्तर से नीचे के पद पर लिअन लिए हुए है, लिअन की अवधि को एकसमान रूप से मौजूदा पांच वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष मान लिया जाए।

3. विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत सीपएसईज़ के बोर्ड में 7 गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दिनांक 28.11.2008 को जांच- समिति की बैठक आयोजित की गई।

4. अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) ने 165 सीपीएसईज़ के संबंध में वर्ष 2017-18 के लिए समझौता- ज्ञापन मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया है (इस माह के दौरान 33 बैठकें आयोजित की गईं)।

5. गोवा में 30 अक्टूबर से 1 नवम्बर, 2018 के दौरान राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् , नई दिल्ली के सहयोग से "सतर्कता जागरूकता/निवारक सतर्कता पद्धतियां" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

6. लोक उद्यम विभाग ने 9 नवम्बर, 2018 को चयनित सीपीएसईज़ के कैपेक्स के लिए मासिक जानकारी प्रधान मंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की ।

****